International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 2, February- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

डॉ. आराधना सक्सेना
सह आचार्य (समाज शास्त्र)
राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.)

सार
निम्न और मध्यम आय वाले देशों की आधी आबादी 2030 तक शहरी क्षेत्रों में रहेगी, और इन संदर्भों में गरीबी और असमानता बढ़ रही है। झुग्गी-झोपड़ी में रहना शहरी अभाव की संकल्पना और वर्णन करने का एक तरीका है, लेकिन झुग्गी बस्ती क्या होती है इसकी कई परिभाषाएँ हैं। यह पेपर अकेले भारत में उपयोग की जाने वाली चार अलग-अलग स्लम परिभाषाओं को प्रस्तुत करता है, जो दर्शाता है कि शहरी अभाव के वितरण और सीमा दोनों का आकलन उस तरीके पर निर्भर करता है जिस तरह से इसकी विशेषता है, जैसा कि सामान्य बाल स्वास्थ्य संकेतकों के साथ स्लम निवास का संबंध है। 2015-2016 तक भारत के राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग करते हुए, सर्वेक्षण में शामिल झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले दो संकेतकों और घरेलू प्रश्नावली से निर्मित दो संकेतकों की तुलना वर्णनात्मक आंकड़ों और उम्र के हिसाब से ऊंचाई और वजन के रैखिक प्रतिगमन मॉडल का उपयोग करके की गई है। स्कोर. परिणाम अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय स्लम परिभाषाओं के बीच तनाव को उजागर करते हैं, और स्लम और शहर के निवासियों की गतिशीलता के अनुभवजन्य प्रतिनिधित्व में सुधार के महत्व को रेखांकित करते हैं।

मुख्य शब्द: शहरी स्लम, स्वास्थ्य

परिचय
दुनिया की आधी से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है और 2030 तक यह अनुमान लगाया गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) के आधे से अधिक निवासी शहरों में निवास करेंगे (मोंटगोमरी, 2008)। जैसे-जैसे ग्रामीण निवासी नौकरियों की तलाश में शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं और शहरी समूहों के विस्तार से गाँवों पर कब्ज़ा हो जाता है, कई निम्न और मध्यम आय वाले देश गरीबी के शहरीकरण से चिंतित हो रहे हैं (प्रधान, 2012)। शहरी विकास का तीव्र और बड़े पैमाने पर विकास सेवाओं के प्रावधान (याच एट अल., 1990) से कहीं आगे निकल गया है और इससे अनौपचारिक बस्तियों का प्रसार हुआ है - और नए, छोटे शहरों का विकास हुआ है (मोंटगोमरी, 2009) - बिना पहुंच के पानी और स्वच्छता, कचरा संग्रहण या कार्यकाल की सुरक्षा के लिए।
केंद्रित शहरी गरीबी और अभाव को अक्सर आवासीय भीड़, पर्यावरणीय खतरों के संपर्क, और सामाजिक विखंडन और बहिष्कार (रैटन, 1995) द्वारा चित्रित किया जाता है, स्थितियों के समूह के सभी घटकों को अक्सर "स्लम निवास" के कैच-ऑल शब्द के साथ संदर्भित किया जाता है। दरअसल, शहरी मुद्दों पर नीति और मीडिया की बयानबाजी मलिन बस्तियों पर केंद्रित होती है क्योंकि उनकी सहज अपील और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित अभाव का अपेक्षाकृत प्राकृतिक वैचारिक सारांश होता है।
"स्लम" शब्द का प्रयोग पहली बार 19वीं सदी की शुरुआत में लंदन में "कम प्रतिष्ठा वाले कमरे" या "शहर के निचले, कम आबादी वाले हिस्सों" का वर्णन करने के लिए किया गया था, लेकिन तब से इसके अर्थ और अनुप्रयोग में कई पुनरावृत्तियां हुई हैं (यूएन-) पर्यावास, 2003बी)। जबकि झुग्गी-झोपड़ी में रहने की शुरुआती परिभाषाओं में शहरी गरीबी के भौतिक, स्थानिक, सामाजिक और यहां तक कि व्यवहारिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है (यूएन-हैबिटैट, 2003ए), हाल ही में संघों का प्रसार कम हो गया है। दरअसल, मानव बस्तियों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएन-हैबिटैट) द्वारा एक मलिन बस्ती को "एक सन्निहित बस्ती" के रूप में फिर से परिभाषित किया गया है, जहां निवासियों को अपर्याप्त आवास और बुनियादी सेवाओं के रूप में जाना जाता है। एक झुग्गी-झोपड़ी को अक्सर सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा शहर के अभिन्न या समान भाग के रूप में मान्यता और संबोधित नहीं किया जाता है" (यूएन-हैबिटैट शहरी सचिवालय और आश्रय शाखा, 2002)। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 2, February- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

करने के लिए लक्ष्य 7 के हिस्से के रूप में मलिन बस्तियों को भी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में शामिल किया है: लक्ष्य 7.डी का लक्ष्य "2020 तक कम से कम 100 मिलियन झुग्गीवासियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण सुधार हासिल करना है।" (संयुक्त राष्ट्र, 2013), क्षेत्र-स्तरीय अभाव और शहरी गरीबी को विकास के एजेंडे में शामिल करना।

एमडीजी की दिशा में प्रगति पर सबसे हालिया रिपोर्ट में यह पाया गया कि लक्ष्य 7.डी को पूरा कर लिया गया है (संयुक्त राष्ट्र, 2013), और अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय ध्यान बाद में कहीं और चला गया है। हालाँकि, इस आशावादी मूल्यांकन को लेकर कई चिंताएँ हैं। सबसे पहले, यह स्पष्ट नहीं है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना वह महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र दावा कर रहा है क्योंकि यह लक्ष्य संभवतः दुनिया भर में झुग्गी-झोपड़ियों की आबादी को कम करके आंकने के आधार पर विकसित किया गया था, जिससे यह दिखने की तुलना में काफी कम आकांक्षापूर्ण हो गया। इसके अतिरिक्त, अन्य लक्ष्यों के विपरीत, 7.डी एक पूर्ण संख्या है, अनुपात नहीं, जिसका अर्थ है कि इसे तब भी पूरा किया जा सकता है जब झुग्गी-झोपड़ियों की आबादी पूर्ण आकार में बढ़ती रहे। यह सचमुच घटित हुआ है; संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 1990 में 650 मिलियन झुग्गीवासी थे; यह संख्या 2000 में 760 मिलियन और 2012 में 863 मिलियन हो गई। संयुक्त राष्ट्र की खोज में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि लक्ष्य 7.डी तक पहुंच गया है, हालांकि, व्यवहार में यह स्थापित करने की चुनौती है कि वास्तव में झुग्गी बस्ती क्या होती है।

मलिन बस्ती परिभाषा

झुग्गी बस्ती को क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा, जैसे वह जो आम तौर पर एक शहरी क्षेत्र का गठन करती है (डोरेलिएन एट अल., 2013), देश (संयुक्त राष्ट्र, 2014), राज्य (आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, 2008) और यहां तक कि अलग-अलग होती है। शहर (ओ'हारे एट अल., 1998)। हाल के शोध ने यह भी संकेत दिया है कि मलिन बस्तियाँ अक्सर अनुमान से कहीं अधिक विषम हो सकती हैं (गोली एट अल., 2011, चन्द्रशेखर और मोंटगोमरी, 2009, अग्रवाल और तनेजा, 2005); फुटपाथ पर रहने वाले जैसे कई गरीब लोग झुग्गियों में नहीं रहते हैं और इसलिए उन्हें मानक परिभाषाओं में "गिना" नहीं जाता है (अग्रवाल, 2011)।

संयुक्त राष्ट्र परिचालन रूप से स्लम को "शहरी क्षेत्र में एक ही छत के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का एक या समूह, जिसमें निम्नलिखित पांच सुविधाओं में से एक या अधिक की कमी है" के रूप में परिभाषित करता है: 1) टिकाऊ आवास (एक स्थायी संरचना जो चरम जलवायु परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती है)); 2) पर्याप्त रहने का क्षेत्र (एक कमरा साझा करने वाले तीन से अधिक लोग नहीं); 3) बेहतर पानी तक पहुंच (ऐसा पानी जो पर्याप्त हो, किफायती हो और अत्यधिक प्रयास के बिना प्राप्त किया जा सकता हो); 4) बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच (एक निजी शौचालय, या उचित संख्या में लोगों के साथ साझा किया जाने वाला सार्वजनिक शौचालय); और 5) सुरक्षित कार्यकाल (वास्तविक या वैधानिक रूप से सुरक्षित कार्यकाल की स्थिति और जबरन बेदखली के खिलाफ सुरक्षा) (यूएन-हैबिटैट, 2006/7)।

जबकि झुग्गी बस्ती के गठन की इस परिभाषा का उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह मूल्यांकन करने के लिए किया गया था कि क्या लक्ष्य 7.डी पूरा किया गया था, यह उन लोगों से काफी अलग है जिनका उपयोग अलग-अलग देशों द्वारा अपनी नीति और योजना उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, युगांडा ने 2008 से स्लम उन्नयन रणनीति और कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने वाले एक दस्तावेज़ में, स्लम को निम्नलिखित विशेषताओं में से एक या अधिक के रूप में परिभाषित किया है: 1) कम आय वाले और/या निम्न स्तर वाले बेरोजगार व्यक्तियों के उच्च घनत्व को आकर्षित करना। साक्षरता, 2) शोर, अपराध, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अनैतिकता (अश्लील साहित्य और वेश्यावृत्ति) और शराब और उच्च एचआईवी/एड्स प्रसार की उच्च दर/स्तर वाला क्षेत्र, या 3) ऐसा क्षेत्र जहां घर पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक भूमि में हैं, उदाहरण के लिए। आर्द्रभूमि (भूमि मंत्रालय, 2008)। संयुक्त राष्ट्र की स्लम परिभाषा को युगांडा के शहरों में लागू करने के परिणामस्वरूप 93% शहरी आबादी झुग्गियों में रहती है।

भारत में, झुग्गी बस्ती के रूप में अधिसूचना, या कानूनी पदनाम, सरकार द्वारा मलिन बस्तियों की मान्यता के लिए केंद्रीय है और समय के साथ इसका उद्देश्य निवासियों को पीने योग्य पानी और स्वच्छता के प्रावधान के अधिकार

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 2, February- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

प्रदान करना है। लेकिन स्पष्ट रूप से झुग्गी-झोपड़ी जैसी विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले कई समुदायों को कभी भी अधिसूचित नहीं किया जाता है (सुब्बारामन एट अल., 2012); उदाहरण के लिए, दिल्ली ने 1994 के बाद से कोई नई मलिन बस्तियां अधिसूचित नहीं की हैं (भान, 2013)। हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा में वैधता शामिल है, और संभवतः सभी वंचित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, न कि केवल सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की, जिससे भारत में झुग्गी निवासियों के वितरण और पूर्ण संख्या पर असहमति हो सकती है।

ये अंतर, साथ ही एमडीजी लक्ष्य 7.डी की पूर्ण प्रकृति, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और स्थानीय सरकारों के बीच अलग-अलग प्राथमिकताओं को जन्म दे सकती है, जिससे यह दावा जटिल हो जाता है कि लक्ष्य 7.डी पूरा हो गया है और इस विकास एजेंडा आइटम को अलग रखा जाना चाहिए। . स्लम के गठन की बहुपक्षीय और देश-स्तरीय परिभाषाओं के बीच तनाव इस पेपर के केंद्रीय शोध प्रश्न को जन्म देता है: क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि स्लम को कैसे परिभाषित किया जाता है? दूसरे शब्दों में, क्या अलग-अलग परिभाषाएँ केंद्रित शहरी अभाव की एक ही अंतर्निहित संरचना पर आधारित हैं और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले समान क्षेत्रों की पहचान करती हैं? यह पेपर निम्नलिखित कारणों से विशेष रूप से भारत के एक संदर्भ में झुग्गी-झोपड़ी में रहने की जांच करेगा:

मलिन बस्तियों की परिभाषा और पहचान भारत सरकार के लिए वर्तमान नीति और कार्यक्रम संबंधी महत्व की है, जो अपने 400 मिलियन शहरी निवासियों के बीच बढ़ती गरीबी, असमानता और खराब स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। भारत सरकार ने राजीव आवास योजना जैसी नीतिगत पहल विकसित की है, जो "झुग्गी मुक्त भारत" (शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, 2010) की परिकल्पना करती है और इसके वितरण और सीमा के दस्तावेज़ीकरण और माप के संबंध में आगे के मार्गदर्शन से लाभ हो सकता है। शहरी गरीब आबादी.

भारत में शहरीकरण, एक अरब से अधिक लोगों के देश में किसी भी व्यापक घटना की तरह, एक विशाल योजना और नीति चुनौती है। 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारत की शहरी आबादी एक दशक में लगभग 32% बढ़ गई (अग्रवाल एट अल., 2007)। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि 2030 तक लगभग 590 मिलियन भारतीय शहरों में रहेंगे, जो आज अमेरिका की आबादी से लगभग दोगुना है (संखे एट अल., 2010); संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 तक देश बहुसंख्यक शहरी होगा। इसलिए भारत में शहरी घटनाओं का अध्ययन पूर्ण आकार और महत्व दोनों में बड़ा है।

इसी प्रकार, भारत के शहरों को देश की वृद्धि और विकास का इंजन कहा गया है। लेकिन मलिन बस्तियों में पाई जाने वाली खराब जीवन स्थितियों का उत्पादकता और मानव पूंजी विकास पर असर पड़ने की संभावना है। उदाहरण के लिए, झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों को पानी प्राप्त करने और सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने के लिए प्रतीक्षा करने में अत्यधिक समय और संसाधन खर्च करते हुए पाया गया है, जिसके गंभीर आर्थिक और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य परिणाम भी होते हैं (सुब्बारामन एट अल., 2014)। मलिन बस्तियों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा की कमी से निवासियों की श्रम शक्ति में भागीदारी और समाज में उनकी भागीदारी कम हो सकती है, दोनों ही देश के विकास पथ पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), भारत का जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2005-2006 में, जनगणना और सर्वेक्षण प्रगणकों दोनों की जानकारी शामिल है कि क्या घर झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में स्थित है, जिससे झुग्गी-झोपड़ियों की परिभाषाओं की तुलना की जा सकती है और भलाई के संकेतकों के साथ उनका जुड़ाव। जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (डीएचएस) जैसे राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षणों के लिए जनगणना से तैयार किए गए जनसंख्या-आधारित नमूना फ्रेम लगभग कभी भी स्लम स्थिति (मोंटाना एट अल।, आगामी) द्वारा स्तरीकृत नहीं होते हैं और सबसे हालिया एनएफएचएस में इन आंकड़ों को शामिल करने से तुलना होती है। भारतीय संदर्भ में झुग्गी-झोपड़ी में रहने की कई परिभाषाएँ संभव हैं।

ऐसे कई अनुभवजन्य अध्ययन हैं जिन्होंने एनएफएचएस में शामिल झुग्गी-झोपड़ी में रहने की दो परिभाषाओं के साथ काम किया है। स्वामीनाथन और मुखर्जी ने पाया कि भारत के आठ शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने और

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 2, February- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

वयस्कों के बीच कम और अधिक वजन के बीच संबंध ने इस्तेमाल की गई परिभाषा (स्वामीनाथन और मुखर्जी, 2012) के आधार पर महत्व और परिमाण दोनों के संदर्भ में अलग-अलग परिणाम दिए। देव और बाल्क दो परिभाषाओं को जोड़ते हैं, जब वे दो मानदंडों (देव और बाल्क, समीक्षाधीन) में से किसी एक को पूरा करते हैं, तो झुग्गियों में रहने वाले परिवारों की पहचान करते हैं। अधिकांश अन्य शोधकर्ताओं ने केवल जनगणना (गौर एट अल., 2013, हजारिका, 2010) या एनएफएचएस (रूबन एट अल., 2012) परिभाषाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना है, हालांकि, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन एनएफएचएस में अंतर्निहित झुग्गी-झोपड़ी परिभाषाएं झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को अनुभवजन्य रूप से चित्रित करने का एकमात्र तरीका नहीं हैं। गुंथर और हार्टजेन ने उप-सहारा अफ्रीका (गुंथर और हार्टजेन, 2012) में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले या नहीं रहने वाले परिवारों को चिह्नित करने के लिए सर्वेक्षण उत्तरदाताओं द्वारा उनके घर और उसके आसपास की बताई गई विशेषताओं का उपयोग किया है, और फ़िंक और उनके सहयोगियों ने 73 देशों में एक समान पद्धति का उपयोग किया है। ग्रामीण, शहरी और झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों के स्वास्थ्य की तुलना करें (फ़िंक एट अल., 2014)। यह पेपर झुग्गी-झोपड़ी में रहने की चार परिभाषाओं की तुलना करके इन अलग-अलग परिभाषाओं को एकीकृत करता है - दो पहले से ही एनएफएचएस प्रश्नावली में शामिल हैं, और दो उत्तरदाताओं की उनके परिवेश के बारे में रिपोर्टों से निर्मित हैं - शहरी भारत में अंतर-शहरी असमानता और इसके निहितार्थों को चित्रित करने के लिए।
झुग्गी-झोपड़ियों में रहने की परिभाषाओं की पहचान करना, तुलना करना और उनका आकलन करना न केवल शहरी नियोजन और एजेंडा-सेटिंग परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य पर क्षेत्र-स्तरीय गरीबी के प्रभाव का दस्तावेजीकरण करने वाले महत्वपूर्ण साहित्य के कारण भी महत्वपूर्ण है, जिनमें से अधिकांश पर आधारित है शहरी भारतीय संदर्भ (अग्रवाल, 2011)।

शहरी अभाव, मलिन बस्तियाँ, और स्वास्थ्य

हालाँकि तंत्र - सामाजिक इंटरैक्टिव, पर्यावरणीय, भौगोलिक, या संस्थागत, बस कुछ का नाम लेने के लिए (गैल्स्टर, 2010) - जिसके द्वारा सामुदायिक स्तर की गरीबी को खराब स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ा जा सकता है, अभी भी जांच के दायरे में हैं, स्लम क्षेत्रों में खराब स्वास्थ्य रहा है मुख्य रूप से उप-सहारा अफ्रीका (बोक्विएर एट अल., 2011, गुंथर और हार्टजेन, 2012) और दक्षिण एशिया, विशेष रूप से बांग्लादेश (ग्रुबनेर एट अल., 2011) और भारत (गौर एट अल., 2013, हजारिका, 2010) में पाए जाते हैं। करीबी रहने वाले क्वार्टर, खराब स्वच्छता, और पीने योग्य पानी तक पहुंच की कमी (स्क्लर एट अल।, 2005), "स्लम-जैसी" समुदायों की सभी विशेषताएं, केवल गरीबों में रहने के प्रभावों के अलावा खराब स्वास्थ्य पैदा करने की संभावना है। घरेलू और अन्य व्यक्तिगत स्तर की विशेषताएँ (चावल और चावल, 2009)। उदाहरण के लिए, भीड़भाड़ निमोनिया, डायरिया और तपेदिक (अनगर और रिले, 2007) जैसी संक्रामक बीमारियों के संचरण को बढ़ावा देती है और पड़ोसियों के खुले में शौच को बच्चों की ऊंचाई (स्पीयर्स, 2013) के साथ नकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाया गया है।
ये स्वास्थ्य चुनौतियाँ स्लम बस्तियों में अनुभव की गई अवैधता और सामाजिक बहिष्कार (डी स्नाइडर एट अल., 2011, सुब्बारामन एट अल., 2012), खराब विनियमित और अप्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं (अग्रवाल एट अल., 2007), पर्यावरण के संपर्क के कारण और बढ़ गई हैं। खतरे (अनगर और रिले, 2007), और भारत सरकार (स्थानीय, राज्य, आदि) के किस स्तर पर सबसे गरीब शहरी निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा और प्रचार के लिए ज़िम्मेदार है, इसके बारे में स्पष्टता की कमी है (नोलन एट अल।, 2014) . कुल मिलाकर, "शहरी मृत्यु दंड" की संभावना, जैसे कि 20वीं शताब्दी में यूरोपीय और अमेरिकी शहरों में औद्योगीकरण के दौरान हुई थी, असंभावित नहीं है (कोंटेह, 2009)।
झुग्गी-झोपड़ी में रहने के निहितार्थों की जांच करने के लिए, यह पेपर मानव और आर्थिक कल्याण के एक संकेतक, बाल स्वास्थ्य (स्ट्रॉस और थॉमस, 1998) पर ध्यान केंद्रित करेगा। हम पिछले महामारी विज्ञान और पोषण संबंधी

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 2, February- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

वातावरण (डीटन, 2007) के प्रभावों की जांच करने के लिए बच्चे की ऊंचाई का उपयोग करते हैं, और तीव्र और वर्तमान स्वास्थ्य और पोषण संबंधी तनावों पर अधिक ध्यान देने के लिए वजन का उपयोग करते हैं। भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं, और विशेष रूप से उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई कम संज्ञानात्मक और शैक्षिक उपलब्धि (हॉडिनॉट एट अल., 2011) के साथ-साथ जीवन भर कम मजदूरी और श्रम बाजार उत्पादकता से जुड़ी हुई है (केस और पैक्ससन, 2008). भारत के साक्ष्य से पता चलता है कि आर्थिक विकास से बाल पोषण में सुधार नहीं हुआ है (डीटन और ड्रेज़, 2009) और पांच साल से कम उम्र के लगभग आधे बच्चे अविकसित हैं (यूनिसेफ, 2013)। अल्पपोषण न केवल बच्चों के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को सीधे प्रभावित करता है, बल्कि यह मलेरिया, निमोनिया और खसरे जैसी संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों में भी शामिल है, जिससे देश में बीमारी के 20 प्रतिशत से अधिक बोझ के लिए अंतर्निहित स्थिति जिम्मेदार हो जाती है (ग्रैग्नोलाटी एट अल।)। 2005).

झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के स्वास्थ्य के अधिकांश अध्ययन विशेष रूप से एक झुग्गी-झोपड़ी में (सुब्बारामन एट अल., 2013), एक शहर में (फोत्सो एट अल., 2013, मोरे एट अल., 2013) या मानकीकृत रोजगार वाले कई देशों में इस विषय की जांच करते हैं। झुग्गी-झोपड़ी में रहना क्या होता है इसकी परिभाषा (फ़िंक एट अल., 2014)। जबकि मोंटगोमरी और हेवेट के एक पेपर ने एनएफएचएस का उपयोग करते हुए पड़ोस की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उम्र के अनुसार ऊंचाई पर प्रभाव (मोंटगोमरी और हेवेट, 2005) की जांच की, लेखक की जानकारी के अनुसार, झुग्गी-झोपड़ी में रहने और बच्चे की ऊंचाई और वजन के बीच संबंध अभी तक सामने नहीं आया है। भारतीय संदर्भ में व्यवस्थित रूप से जांच की गई।

स्लम क्षेत्र

स्लम क्षेत्र का आशय सार्वजनिक भूमि पर अवैध शहरी बस्तियों से है और आमतौर पर यह एक निश्चित अवधि के दौरान निरंतर एवं अनियमित तरीके से विकसित होता है। स्लम क्षेत्रों को शहरीकरण का एक अभिन्न अंग माना जाता है और शहरी क्षेत्र में समग्र सामाजिक-आर्थिक नीतियों एवं योजनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

'स्लम क्षेत्र' को प्रायः 'अराजक रूप से अधिग्रहीत, अव्यवस्थित रूप से विकसित और आमतौर पर उपेक्षित क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहाँ काफी अधिक आबादी निवास करती है।

'स्लम क्षेत्र' के अस्तित्व और तीव्र विकास को एक सामान्य शहरी घटना के रूप में देखा जाता है, जो कि दुनिया भर में प्रचलित है।

प्रमुख बिंदु

शहरीकरण

शहरीकरण का आशय ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी और इस परिवर्तन को अपनाने हेतु समाज के तरीकों से है।

शहरों को प्रायः तीव्र शहरीकरण के प्रतिकूल परिणामों जैसे- अत्यधिक जनसंख्या, आवास और बुनियादी सुविधाओं की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोज़गारी तथा सामाजिक अशांति आदि का सामना करना पड़ता है।

विकसित शहर के निर्माण के इस मॉडल में अनियोजित विकास भी शामिल होता है, जो अमीर और गरीब समुदाय के बीच व्याप्त द्वंद्व को मज़बूत करता है।

इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने शहरों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले शहरी गरीबों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिये परेशानी को और गंभीर कर दिया है।

स्लम क्षेत्रों की स्थिति

भारत में 13.7 मिलियन स्लम घरों में कुल 65.49 मिलियन लोग निवास करते हैं। लगभग 65% भारतीय शहरों के आसपास झुग्गियाँ और स्लम क्षेत्र मौजूद हैं, जहाँ लोग काफी घनी बस्तियों में रहते हैं।

'नेशनल सर्विस स्कीम राउंड' (जुलाई 2012-दिसंबर 2012) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2012 तक दिल्ली में लगभग 6,343 स्लम बस्तियाँ थीं, जिनमें दस लाख से अधिक घर थे, जहाँ दिल्ली की कुल आबादी का 52% हिस्सा

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 2, February- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

निवास करता था।

स्लम निवासियों पर कोविड-19 का प्रभाव

वित्तीय असुरक्षा

भारत की लगभग 81 प्रतिशत आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती है। संपूर्ण कोविड लॉकडाउन के अचानक लागू होने से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की आजीविका काफी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

पूर्व लॉकडाउन के बाद दिल्ली में भारी संख्या में 'रिवर्स माइग्रेशन' देखा गया, जब हज़ारों प्रवासी कामगार अपने गृहनगर वापस चले गए। इस दौरान लगभग 70% स्लम निवासी बेरोज़गार हो गए; 10% की मज़दूरी में कटौती हुई और 8% पर इसके अन्य प्रभाव देखे गए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र योजना कवरेज:

यद्यपि ग्रामीण निवासियों का एक बड़ा वर्ग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से उपलब्ध खाद्यान्न के कारण महामारी से प्रेरित आर्थिक व्यवधान का सामना करने में सक्षम था, किंतु शहरी गरीबों तक ऐसे राशन की पहुँच न्यूनतम थी।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी ग्रामीण गरीबों के बीच शहरी गरीबों की तुलना में बेहतर कवरेज था। शहरी क्षेत्रों में परिवारों के एक बड़े हिस्से के पास राशन कार्ड नहीं है।

मौजूदा असमानताएँ:

कोविड-19 महामारी ने झुग्गियों और स्लम क्षेत्रों की चुनौतियों को और अधिक गंभीर रूप से उजागर किया है। इन क्षेत्रों में हाथ धोना और शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना असंभव था।

दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लगभग 21.8% परिवार सार्वजनिक नल जैसे साझा जल स्रोतों पर निर्भर हैं।

पोषण और भूख:

पोषण की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट शहरी निवासियों के मामले में अधिक देखी गई और अधिकांश लोगों को भोजन खरीदने तक के लिये पैसे उधार लेने पड़ रहे थे।

कुल मिलाकर भूख और खाद्य असुरक्षा का स्तर काफी उच्च बना रहा, जहाँ स्थिति में सुधार की उम्मीद काफी कम थी और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ खाद्य सहायता प्रदान करने संबंधी उपायों की भी कमी थी।

स्लम विकास की उपेक्षा से उत्पन्न मुद्दे:

रोगों के प्रति संवेदनशील:

स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोग टाइफाइड और हैजा जैसी जलजनित बीमारियों के साथ-साथ कैंसर व एचआईवी/एड्स जैसी अधिक घातक बीमारियों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं।

सामाजिक कुरीतियों के शिकार:

ऐसी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों को वेश्यावृत्ति, भीख मांगने और बाल तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा ऐसी बस्तियों में रहने वाले पुरुषों को भी इन सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ता है।

अपराध की घटनाएँ:

स्लम क्षेत्रों को आमतौर पर ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है, जहाँ अपराध काफी अधिक होते हैं। यह स्लम क्षेत्रों में शिक्षा, कानून व्यवस्था और सरकारी सेवाओं के प्रति आधिकारिक उपेक्षा के कारण है।

गरीबी

एक विकासशील देश में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अपना जीवन यापन करते हैं जो न तो उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और न ही बेहतर जीवन के लिये पर्याप्त आय उपलब्ध कराता है, जिससे वे गरीबी के दुष्चक्र में फँस जाते हैं।

निष्कर्ष

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 2, February- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

नतीजे बताते हैं कि जिस तरह से स्लम पदनाम को परिभाषित किया गया है वह शहरी आबादी के वर्णनात्मक लक्षण वर्णन के साथ-साथ सामुदायिक नुकसान और बाल स्वास्थ्य के बीच अनुभवजन्य सहयोग के परिमाण और महत्व दोनों के लिए मायने रखता है। दरअसल, स्लम परिभाषाओं के बीच महत्वपूर्ण विसंगति है कि किस घर को स्लम में स्थित माना जाए। ये परिणाम दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि स्लम आवास की अवधारणा और माप के लिए शब्द की नीति प्रासंगिकता को देखते हुए और अधिक सैद्धांतिक और अनुभवजन्य कार्य की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा, जिसका उपयोग देशों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने की तुलना करने के लिए किया जाता है, और नीति और योजना उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत देश (जैसे भारत) के केंद्रित शहरी नुकसान के स्तर की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषाओं के बीच बेमेल होने से भिन्न और यहां तक कि परस्पर विरोधी निष्कर्ष और विकास प्राथमिकताएं हो सकती हैं।

संदर्भ

अग्रवाल सिद्धार्थ। भारत में शहरी स्वास्थ्य की स्थिति; चयनित राज्यों और शहरों में सबसे गरीब चतुर्थक की बाकी शहरी आबादी से तुलना करना। पर्यावरण और शहरीकरण. 2011;23:13-28.

अग्रवाल सिद्धार्थ, सत्यवदा अरविंद, कौशिक एस, कुमार राजीव। शहरीकरण, शहरी गरीबी और शहरी गरीबों का स्वास्थ्य: स्थिति, चुनौतियाँ और आगे का रास्ता। जनसांख्यिकी भारत. 2007;36:121-134.

अग्रवाल सिद्धार्थ, तनेजा शिवानी। सभी मलिन बस्तियाँ समान नहीं हैं: शहरी गरीबों के बीच बाल स्वास्थ्य की स्थिति। भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ. 2005;42:233-44.

भान गौतम. नियोजित अवैधताएँ: दिल्ली में आवास और योजना की 'विफलता': 1947-2010। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. 2013;XLVII:58-70।

भौमिक सौम्यदीप। भारत ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। लैंसेट. 2012;380:550।

बोकिएर फिलिप, बेगुय डोनाटियन, ज़ुलु एलिया एम, मुइंडी कान्यिवा, कोन्सिगा अदामा, ये याज़ौमे। क्या स्लम बस्तियों में प्रवासी बच्चों को अधिक स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है? नैरोबी, केन्या से साक्ष्य। शहरी स्वास्थ्य जर्नल. 2011;88(सप्ल 2):एस266-81।

ब्रॉकरहॉफ़ मार्टिन। बड़े शहरों में बच्चों का अस्तित्व: प्रवासियों के नुकसान। सामाजिक विज्ञान एवं चिकित्सा. 1995;40:1371-83.

केस ऐनी, पैक्ससन क्रिस्टीना। कद और स्थिति: ऊंचाई, क्षमता और श्रम बाजार के परिणाम। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जर्नल. 2008;116:499-532.

चंद्रशेखर एस, मोंटगोमरी मार्क आर. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट (आईआईईडी) लंदन के लिए तैयार किया गया पेपर: आईआईईडी; 2009. भारत में गरीबी की परिभाषाओं का विस्तार: बुनियादी जरूरतें और शहरी आवास।

क्लेलैंड जॉन, बर्नस्टीन स्टेन, एज़ेह एलेक्स, फाउंडेस एनीबल, ग्लेशियर अन्ना, इनिस जोलेन। परिवार नियोजन: अधूरा एजेंडा. नश्तर। 2006;368:1810-1827।

करी जेनेट, वोगल टॉम। विकासशील देशों में प्रारंभिक जीवन स्वास्थ्य और वयस्क परिस्थितियाँ। अर्थशास्त्र की वार्षिक समीक्षा. 2013;5:1-36.

डेहली डेरेन लॉरेंस, अडायर लिंडा एस. शहरी पर्यावरण की मात्रा निर्धारित करना: शहरीता का एक पैमाना शहरी-ग्रामीण द्वंद्व से बेहतर प्रदर्शन करता है। सामाजिक विज्ञान एवं चिकित्सा. 2008;64:1407-1419।

डी स्नाइडर, नेली सालगाडो वी, फ्रेल शेरोन, फोत्सो जीन, खादर ज़ेनब, मेरेसमैन सर्जियो, मोंगे पेट्रीसिया, पाटिल-देशमुख अनीता। सामाजिक स्थितियाँ और शहरी स्वास्थ्य असमानताएँ: अनुसंधान और कार्रवाई के माध्यम से शहरी परिदृश्य को बदलने की वास्तविकताएँ, चुनौतियाँ और अवसर। शहरी स्वास्थ्य जर्नल. 2011;88:1183-1193।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 2, February- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

डीटन एंगस। ऊंचाई, स्वास्थ्य और विकास. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। 2007;104:13232-37।
डीटन एंगस। ऊंचाई, स्वास्थ्य और असमानता: भारत में वयस्कों की ऊंचाई का वितरण। अमेरिकी आर्थिक समीक्षा: कागजात और कार्यवाही। 2008;98:468-474.
डीटन एंगस, ड्रेज़ जीन। भारत में भोजन और पोषण: तथ्य और व्याख्याएँ। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. 2009;XLIV:42-65.